क्या आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की जा सकती है ?

राम पुनियानी

अगस्त 2018 के विदेश दौरे के दौरान, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ स्ट्रेटेजिक स्टडीज को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ''आरएसएस भारत का मिजाज बदलना चाहता है। भारत में कोई भी अन्य ऐसी संगठन नहीं है, जो देश की सभी संस्थाओं पर कब्जा करना चाहता हो...आरएसएस की विचारधारा, अरब देशों के मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी है। इसका लक्ष्य यह है कि सभी संस्थाओं की केवल एक ही विचारधारा हो और यह विचारधारा, अन्य सभी विचारधाराओं को कुचल द''। उन्होंने यह भी कहा कि ''मुस्लिम ब्रदरहुड पर अनवर सादात की हत्या के बाद पाबंदी लगा दी गई थी और गांधी की हत्या के बाद आरएसएस को प्रतिबंधित कर दिया गया था...और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों ही संगठनों में महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता''। इस बयान का जवाब देते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, ''राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी संघ से जुड़े थे और राहुल गांधी की संघ की मुस्लिम ब्रदरहुड से तुलना अक्षम्य है''।

संघ से जुड़े कुछ व्यक्तियों ने कहा कि जिसने भारत को न समझा हो, वह आरएसएस को नहीं समझ सकता। आरएसएस की राजनीति की प्रकृति के कई विभिन्न विश्लेषण उपलब्ध हैं। राजनीति विज्ञानियों एवं शिक्षाविदों ने आरएसएस की गतिविधियों के पीछे की राजनीति को उजागर किया है। आरएसएस न केवल एक राजनीतिक संस्था है वरन् वह उससे भी आगे बढ़ कर है। उसकी राजनीतिक शाखा, भाजपा, उसके उन क्रियाकलापों का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है जो उससे जुड़ी हुई असंख्य संस्थाएं करती हैं। भाजपा के सुधांशु मित्तल ने अपने एक लेख में कहा है कि संघ परिवार की संस्थाओं ने देश के लिए बहुत कुछ किया है।

भारत में आरएसएस से जुड़ी सैकड़ों संस्थाएं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। हम यहां इन संस्थाओं की संदिग्ध एवं जोड़तोड़ वाली गतिविधियों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम केवल इस पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं कि ये संस्थाएं ऐसा क्या नहीं कर रही हैं, जो समाज के विभिन्न वर्गों के हित में ज़रूरी है और जो इन्हें करना चाहिए। उदाहरण के लिए, हम आरएसएस से जुड़ी संस्था भारतीय किसान संघ की बात करें। हम देख रहे हैं कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जो गहन कृषि संकट का प्रतीक है। क्या हमने कभी इस संस्था को इस मुद्दे पर बात करते हुए सुना कि कृषि क्षेत्र को बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए और किस तरह सरकार की गलत नीतियों के कारण गांवों की दुर्दशा हो रही है। यही सवाल संघ परिवार की उन संस्थाओं के बारे में भी उठाया जा सकता है, जो आदिवासी क्षेत्रों में सक्रिय हैं। आदिवासी क्षेत्रों में बढ़ती ईसाई-विरोधी हिंसा की खबरें तो मिलती हैं, लेकिन हमने कभी इन संस्थाओं को आदिवासियों के विस्थापन एवं हाशिए पर खिसकते जाने की बात करते नहीं सुना।

आरएसएस परोपकारी गतिविधियों में बढ़-चढ़कर शामिल होने का दावा करता है। मीडिया में ऐसी खबरें आती रहती हैं कि आरएसएस के कार्यकर्ता किसी भी आपदास्थल पर सबसे पहले पहुंचते हैं। लेकिन हमें केरल में तो यह नजर नहीं आया! यह जानना दिलचस्प होगा कि मुस्लिम ब्रदरहुड भी परोपकारी गतिविधियां करता है परंतु दोनों ही मामलों में ये परोपकारी गतिविधियां सतही होती हैं और इनका मुख्य लक्ष्य एक विशेष प्रकार के सामाजिक रिश्तों को समाज पर लादना होता है। मूलतः, आरएसएस और मुस्लिम ब्रदरहुड दोनों का लक्ष्य ऐसे समाज की स्थापना करना है जो समानता के प्रजातांत्रिक मूल्य के विरुद्ध हो। निश्चित तौर पर आरएसएस और मुस्लिम ब्रदरहुड जुड़वां नहीं हैं परंतु उनमें अनेक समानताएं हैं, जिनमें से सबसे बड़ी यह है कि दोनों का राजनैतिक एजेंडा एक है। अपनी सारी बड़ी-बड़ी बातों के बावजूद, आरएसएस का मूल एजेंडा हिन्दू राष्ट्र की स्थापना है। वह भारतीय संविधान के मूल्यों को पश्चिमी मानता है और समाज को उन मूल्यों के आधार पर संचालित करना चाहता है जो हिन्दू पवित्र ग्रंथों में दिए गए हैं।

अब हम देखें कि मुस्लिम ब्रदरहुड के क्या लक्ष्य हैं। वह भी समानता के प्रजातांत्रिक मूल्यों व प्रजातांत्रिक संस्थाओं को पश्चिमी बताता है और कहता है कि इस्लामिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उसके लिए इस्लामिक मूल्यों का अर्थ है लैंगिक और सामाजिक असमानता।

दोनों के द्वार केवल पुरुषों के लिए खुले हैं, दोनों स्वर्णिम अतीत की बातें करते हैं और आधुनिक मूल्यों (जिन्हें वे पश्चिमी बताते हैं) के विरोधी हैं। यह तो हुई दोनों संस्थाओं के बीच समानताएं।

आरएसएस ने प्रशिक्षित प्रचारकों की एक बड़ी फौज तैयार कर ली है जो विभिन्न संस्थाओं का गठन करती है और उनके जरिए आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाती है। इसके विपरीत, मुस्लिम ब्रदरहुड केवल अपने झंडे तले काम करता है। यहां यह जोड़ा जा सकता है कि अमरीका में सन् 1920 के दशक में उदित ईसाई कट्टरतावाद भी कुछ इसी तरह का था। अनेक देशों में औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के बाद ऐसे संगठनों ने जन्म लिया जो धर्म को अपनी वैधता का आधार बनाते हैं और समानता के मूल्य के विरुद्ध हैं। भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1885 में अपनी स्थापना के बाद से ही एक समावेशी राष्ट्र के निर्माण की दिशा में काम करना शुरू किया, जिसमें सभी धर्मों के लोगों के लिए स्थान था। कांग्रेस, सामाजिक समानता की हामी थी।

इसके विपरीत, मुस्लिम लीग और हिन्दू महासभा-आरएसएस का गठन सामंती और जमींदार वर्गों ने किया और बाद में इनमें समाज के श्रेष्ठि और मध्यम वर्ग का एक तबका शामिल हो गया। ये दोनों ही संस्थाएं स्वर्णिम अतीत का महिमामंडन करती हैं और अपने-अपने धर्मों के ग्रंथों और राजाओं के शासन को सर्वश्रेष्ठ बताती हैं। आरएसएस ने बड़ी चतुराई से दर्जनों ऐसे संगठन बना लिए हैं जिससे उसके प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं के बीच श्रम विभाजन हो गया है और अब वे समाज के विभिन्न तबकों में हिन्दू राष्ट्र के एजेंडे को लागू करने और भारतीय संविधान में निहित मूल्यों का विरोध करने में जुटे हुए हैं।

संबित पात्रा ने राहुल गांधी के वक्तव्य को अक्षम्य बताया और यह कहा कि कोविंद, मोदी, वाजपेयी इत्यादि की संघी पृष्ठभूमि है। यह कहना मुश्किल है कि उन्होंने यह क्यों नहीं बताया कि महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे, पास्टर स्टेन्स और उनके दो बच्चों को जिंदा जलाने वाला दारासिंह और प्रमोद मुतालिक, जिनकी श्रीराम सेना ने पब में जाने वाली लड़कियों पर हमले किए थे, की भी या तो संघी पृष्ठभूमि थी या उनका संघ से कोई जुड़ाव था। मुस्लिम ब्रदरहुड को कई देशों में आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है और आरएसएस के दो प्रचारक अजमेर धमाकों के सिलसिले में जेल में हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं कि ये दोनों केवल पुरुषों की ऐसी संस्थाएं हैं जो प्रजातांत्रिक मूल्यों की विरोधी हैं और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए धार्मिक पहचान का उपयोग करती हैं। उनके सांगठनिक ढांचे और काम करने के तरीके में कुछ मामूली अंतर हो सकते हैं।

हिंडेनबर्ग/अदाणी : खबरों की बारिश से दबाई जाने वाली सच्चाई

दिव्यांशी मिश्रा

हिंडेनबर्ग रिपोर्ट के जारी होने के बाद भारत के स्टॉक एक्सचेंजों में भूचाल-सा आ गया। रिपोर्ट जारी होने के एक सप्ताह के भीतर ही अडाणी समूह की कम्पनियों के शेयर के मूल्य में 30 प्रतिशत यानी 120 अरब डॉलर तक की गिरावट देखने में आयी। दुनिया का तीसरे नम्बर का सबसे अमीर आदमी देखते ही देखते इतना फिसल गया कि अब उसकी गिनती शीर्ष 20 अमीरों में भी नहीं हुई। अमेरिकी 'एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर' संस्था हिंडेनबर्ग की इस रिपोर्ट में तथ्यों और आंकड़ों के साथ यह उजागर किया गया है कि अडाणी समूह ने इतने कम समय में जो पूँजी का साम्राज्य खड़ा किया है उसके पीछे दशकों से स्टॉक कीमतों और बही-खातों की हेराफेरी, विदेशी 'टैक्स हैवेन' में मौजूद अपने परिजनों द्वारा संचालित फ़र्ज़ी शेल कम्पनियों के ज़रिए अपने पैसे को अपनी ही कम्पनी में फिर से निवेश करके उसके शेयर की क़ीमतों को बढ़ाने और इन ऊँची शेयर क़ीमतों को दिखाकर देश और दुनिया की तमाम वित्तीय संस्थाओं से भारी-भरकम क़र्ज़ लेने की तिकड़म काम कर रही है।

अडाणी समूह पर इस प्रकार के फ़र्ज़ीवाड़े के आरोप पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन अब तक यह लुटेरा समूह सरकार में अपनी पहुँच और मानहानि के मुक़दमों का सहारा लेते हुए मामले को रफ़ा-दफ़ा करता आया था या फिर जाँच-पड़ताल की क़वायद करते हुए मामले को ठण्डे बस्ते में डाल दिया जाता था। लेकिन इस बार ऊँट को पहाड़ के नीचे आना पड़ा क्योंकि अबकी बार आरोप एक अन्तरराष्ट्रीय संस्था ने लगाया है और अब तमाम देशी-विदेशी निवेशकों व क़र्ज़दाताओं का भरोसा भी डगमगाता दिख रहा है जो शेयर बाज़ार में आये भूचाल से स्पष्ट है।

इस भरोसे को बरक़रार रखने के लिए अडाणी ने हिंडेनबर्ग की रिपोर्ट का एक हास्यास्पद जवाब भी दिया और रिपोर्ट के बाद लाये गये फ़ॉलो-ऑन पब्लिक ऑफ़र से प्राप्त रक़म को निवेशकों को वापस लौटा दिया। लेकिन फिर भी अडाणी समूह की कम्पनियों के शेयरों में औंधे मुँह हो रही गिरावट नहीं थमी।

ग़ौरतलब है कि हिंडेनबर्ग रिसर्च एक 'एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर' संस्था है। 'शॉर्ट सेलिंग' का मतलब होता है कि किसी कम्पनी के शेयर को पहले अधिक दाम पर बेचकर बाद में कम दाम पर ख़रीदकर मुनाफ़ा कमाना। हिंडेनबर्ग इस प्रकार की 'शॉर्ट सेलिंग' करने से पहले किसी कम्पनी द्वारा शेयर बाज़ार में की जा रही धाँधली पर शोध करती है और यह सुनिश्चित करने के बाद कि उस कम्पनी के शेयर का मूल्य उसके वास्तविक मूल्य से ज़्यादा है, वह अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक करती है जिसके नतीजे के रूप में उस कम्पनी के शेयर का मूल्य गिरने लगता है और इस गिरावट का फ़ायदा उठाते हुए वह पहले अधिक दाम पर बेचे गये उसके शेयर को कम दाम पर वापस ख़रीदकर मुनाफ़ा कमाती है।

स्पष्ट है कि हिंडेनबर्ग रिसर्च का मक़सद बड़ी कम्पनियों के घोटालों को उजागर करके मुनाफ़ा कमाना ही है। लेकिन इस प्रक्रिया में आज के दौर में पूँजीवादी लूट-खसोट का एक पहलू हमारे सामने अवश्य आता है।

हिण्डेनबर्ग रिसर्च ने अडाणी समूह की कम्पनियों पर 2 वर्ष तक किये गये अपने शोध की रिपोर्ट में दावा किया है कि अडाणी समूह की 7 लिस्टेड कम्पनियों के स्टॉक में पिछले 3 वर्षों के दौरान जो औसतन 819 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है वह जालसाज़ी के ज़रिए हुई है। इस जालसाज़ी का तरीक़ा बताते हुए रिपोर्ट में प्रमाणों के साथ दिखाया गया है कि अडाणी समूह ने 'टैक्स हैवेन' कहे जाने वाले मॉरीशस, साइप्रस, यूएई, सिंगापुर और कैरिबियाई द्वीप समूह के तमाम देशों में फ़र्ज़ी शेल कम्पनियों का जाल बिछाया है जिन्हें गौतम अडाणी का बड़ा भाई विनोद अडाणी नियंत्रित करता है।

विदेशों में मौजूद इन फ़र्ज़ी कम्पनियों में ग़ैर-क़ानूनी रूप से अडाणी समूह का ही पैसा लगा है और इसी पैसे से वापस भारत में अडाणी की ही लिस्टेड कम्पनियों के शेयर ख़रीदे जाते हैं और इस प्रकार इन कम्पनियों के शेयर की माँग में बढ़ोत्तरी करके उसके मूल्य को कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है।

भारतीय शेयर बाज़ार के विनियामक सेबी (सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इण्डिया) के नियम के अनुसार किसी लिस्टेड कम्पनी के शेयरों में प्रमोटर्स का हिस्सा 75 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। लेकिन शेल कम्पनियों के उपरोक्त फ़र्ज़ीवाड़े की मदद से अडाणी की 7 लिस्टेड कम्पनियों में अडाणी परिवार की हिस्सेदारी 75 प्रतिशत से कहीं ज़्यादा हो जाती है।

यही नहीं अडाणी समूह अपनी कम्पनियों के शेयर के ऊँचे मूल्य और उनकी अच्छी सेहत दिखाकर देशी व विदेशी वित्तीय संस्थाओं से भारी क़र्ज़ भी लेता रहा है जिसकी राशि उसकी वास्तविक परिसम्पत्तियों के मूल्य की तुलना में कहीं ज़्यादा है।

इस प्रकार अडाणी समूह की कम्पनियों के शेयर के मूल्य उनकी वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाते हैं बल्कि उनकी वास्तविक स्थिति पर पर्दा डालने का काम करते हैं।

ग़ौरतलब है कि अडाणी समूह के शेयरों में निवेश करने वालों में एलआईसी जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियाँ भी शामिल हैं। एलआईसी ने अडाणी समूह की कम्पनियों में 74 हज़ार करोड़ रुपये का निवेश किया है। यानी आम जनता अपनी आमदनी में से कटौती करके जीवन बीमा के लिए जो प्रीमियम भरती है उसका अच्छा-ख़ासा हिस्सा अडाणी की ऐसी कम्पनियों में लगा है जिनमें धोखाधड़ी हुई है। इसी प्रकार अडाणी की कम्पनियों को क़र्ज़ देने वाली वित्तीय संस्थाओं में एसबीआई और पीएनबी जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी शामिल हैं।

एसबीआई ने अडाणी समूह को 21 हज़ार करोड़ रुपये का क़र्ज़ा दिया है और पीएनबी ने 7 हज़ार करोड़ रुपये का। अगर अडाणी समूह की कम्पनियाँ डूबती हैं तो उसका असर केवल उसकी कम्पनियों और उसके कर्मचारियों पर ही नहीं बल्कि एसबीआई, पीएनबी और एलआईसी जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों पर भी होगा, यानी उसका असर आम जनता की ज़िन्दगी पर भी होगा और पहले से ही मंदी के ख़तरे से जूझ रही भारतीय अर्थव्यवस्था की अस्थिरता भी और बढ़ेगी।

हिंडेनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो सच्चाइयाँ उजागर हुई हैं वो केवल अडाणी के ही नहीं बल्कि समूची पूँजीवादी व्यवस्था के लुटेरे चरित्र को एक बार फिर से बेपर्दा करती हैं। इतने बड़े घोटाले के सामने आने के बाद यह सवाल उठना लाज़िमी है कि आखिर अडाणी जैसा जालसाज़ जब दशकों से यह गोरखधन्धा कर रहा था तब तमाम सरकारी एजेंसियाँ क्या कर रही थीं? मोदी सरकार के विरोधियों के मामूली मामलों में भी ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियाँ तुरन्त छापा मारने पहुँच जाती हैं, लेकिन कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला दशकों से चलता रहा और किसी भी एजेंसी ने चूँ तक नहीं बोली।

शेयर बाज़ार की गतिविधियों पर निगरानी करने वाली एजेंसी सेबी ने भी इतने सालों में अडाणी समूह पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। ऐसा नहीं था कि अडाणी की करतूतों के बारे में किसी को कोई भनक नहीं थी। हिंडेनबर्ग रिपोर्ट में जो आरोप लगाये गये हैं वैसे आरोप पहले भी अडाणी समूह पर लगते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इस लुटेरे पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात तो यह है कि सिर से लेकर पाँव तक भ्रष्टाचार में डूबा यह लुटेरा इस देश के प्रधानमंत्री का जिगरी यार है। ग़ौरतलब है कि यह वही प्रधानमंत्री है जिसने सत्ता में पहुँचने से पहले भ्रष्टाचार और काले धन को लेकर बहुत शोर मचाया था और लम्बे-चौड़े वायदे किये थे। यह प्रधानमंत्री निहायत ही बेशर्मी से अपने जिगरी यार के निजी जेट में सवारी करता है और उसको राष्ट्र की समृद्धि का जनक बताकर उसका महिमामंडन करता है। 'सइयाँ भए कोतवाल, अब डर काहे का!' की कहावत को चरितार्थ करते हुए अडाणी ने ख़ास तौर पर मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी पूँजी के अम्बार में ज़बर्दस्त बढ़ोत्तरी की है।

कोरोना महामारी के दौरान जब पूरे देश की जनता त्राहि-त्राहि कर रही थी तब इस लुटेरे ने अपने जिगरी यार की सलाह को शब्दशः मानते हुए आपदा में ज़बर्दस्त अवसर तलाशा और अपनी सम्पत्ति में 8 गुना इज़ाफ़ा कर लिया।

इस बीच पूरा पूँजीवादी मीडिया इस जालसाज़ लुटेरे को देश का रोल-मॉडल बताता रहा, उसकी कामयाबी की 'गौरव-गाथाएँ' पूरे समाज में सुनियोजित ढंग से फैलायी जाती रहीं। लोगों को बताया जाता रहा कि इस व्यवस्था में कोई भी आदमी अपनी मेहनत और बुद्धि के बूते अमीर बन सकता है। लेकिन अब सच्चाई चीख़-चीख़कर हमें बता रही है कि पूँजीवादी समाज में जिन्हें रोल-मॉडल बताया जाता है उनकी कामयाबी के पीछे भाँति-भाँति की लूट-खसोट छिपी होती है।

बैंकों व वित्तीय संस्थाओं में जमा जनता की बचत को ये क़र्ज़ों के रूप में इस्तेमाल करते हुए अपनी पूँजी बढ़ाते हैं। इस पूँजी से कच्चा माल, मशीनें और श्रम-शक्ति ख़रीदते हैं। सरकार से अपनी क़रीबी का फ़ायदा उठाते हुए ये औने-पौने दामों पर ज़मीन, लाइसेंस व विभिन्न प्रकार के ठेके हासिल करते हैं। उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान मज़दूरों के श्रम को लूटकर ये मुनाफ़ा कमाते हैं।

उसके बाद जब कर देने की बारी आती है तो सरकार पर दबाव बनाकर करों में ज़बर्दस्त छूट हासिल करते हैं जिससे आम मेहनतकश जनता पर बोझ बढ़ता है और उसकी आमदनी और जीवन की गुणवत्ता में गिरावट होती है। इस अपार लूट से भी जब इन लुटेरों को सन्तोष नहीं होता तो वे भाँति-भाँति की तिकड़मों के ज़रिए स्टॉक कीमतों व बही-खाते में हेराफेरी करके अपनी लूट के पहाड़ को और ऊँचा करने से भी नहीं चूकते हैं।

इस नज़रिए से देखने पर हम पाते हैं कि हिंडेनबर्ग रिपोर्ट में जो सच्चाइयाँ उजागर हुई हैं वो दरअसल इस व्यवस्था की कुल लूट के आइसबर्ग का टिप मात्र हैं। कुछ लोग इस व्यवस्था को थोड़ा विनियमित करके इसकी लूट पर नकेल कसने की वकालत करते हैं। लेकिन वित्तीय पूँजी के इस मौजूदा युग में पूँजीवादी व्यवस्था इतनी सड़ चुकी है कि यह मानवता के सामने विकल्प के रूप में विभिन्न प्रकार की लूट-खसोट ही दे सकती है।

इसलिए आज ज़रूरत इस लुटेरी व्यवस्था में रंगरोगन करके इसे मानवीय रूप देने की नहीं बल्कि इसका पर्दाफ़ाश करते हुए इसे जड़ से उखाड़ फेंकने की है।